नईदुनिया

खास-खबरें

गुम फोन लौटाने के बहाने बैंक खाते खाली कर रहे साइबर ठग

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: साइबर अपराधियों ने ठगी का नया तरीका अपनाया है, जिसमें वे गुम हुए मोबाइल फोन को वापस करने का झांसा देकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इस तरह की ठगी को हाइब्रिड साइबर फ्रॉड कहा जा रहा है, जिसमें अपराधी कई तरीकों को मिलाकर लोगों से धोखाधड़ी करते हैं। इस फ्रॉड में ठग पहले किसी व्यक्ति के खोए हुए फोन या उससे जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद वे फोन मिलने का दावा करते हुए पीड़ित से संपर्क करते हैं और भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। बातचीत के दौरान वे निजी जानकारी, बैंक संबंधी विवरण या ओटीपी जैसी संवेदनशील जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। साइबर अपराधी कई बार फर्जी लिंक भेजकर या मोबाइल एप डाउनलोड करने के लिए कहकर भी लोगों को जाल में फंसाते हैं। लिंक पर क्लिक करने या जानकारी साझा करने के बाद ठग बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक जानकारी, पासवर्ड, ओटीपी या यूपीआई पिन साझा न करें। यदि कोई व्यक्ति फोन लौटाने के नाम पर लिंक भेजता है।

हिंदुस्तान कॉपर में हिस्सेदारी बेच रही सरकार, निवेशकों को ऑफर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार की ओर से कंपनी में करीब 6 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए ओएफएस जारी किया गया है। यह ऑफर रिटेल निवेशकों के लिए भी खोला गया है। ओएफएस के तहत सरकार कंपनी के शेयर बेचकर हिस्सेदारी कम करेगी। बुधवार से रिटेल निवेशकों के लिए यह प्रक्रिया शुरू हुई है। निवेशक तय नियमों के अनुसार इस ऑफर में हिस्सा ले सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबा उत्पादन क्षेत्र की प्रमुख सरकारी कंपनी है। सरकार समय-समय पर विनिवेश प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करती रही है। इसके माध्यम से सरकार को राजस्व प्राप्त होता है और बाजार में निवेश के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। ऑफर फॉर सेल में मौजूदा शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी के कुछ शेयर सीधे बाजार के माध्यम से बेचते हैं।

रिकॉर्ड घाटे के बाद एयर इंडिया को नई फंडिंग की जरूरत, मालिकों से मांगे 1.5 अरब डॉलर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: एयर इंडिया अपने कारोबार को मजबूत करने और टर्नअराउंड योजना को आगे बढ़ाने के लिए नई फंडिंग जुटाने की तैयारी कर रही है। रिकॉर्ड घाटे के बाद एयरलाइन ने अपने मालिकों से करीब 1.5 अरब डॉलर यानी लगभग 14,355 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाने की मांग की है। एयर इंडिया को वित्त वर्ष 2025 में करीब 22 हजार करोड़ रुपये के घाटे का सामना करना पड़ा है। इसके बाद कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने और परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पूंजी की जरूरत महसूस कर रही है। एयर इंडिया की टर्नअराउंड योजना के तहत कंपनी अपने बेड़े के विस्तार, सेवा सुधार और परिचालन को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। इसके लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी।

चीनी की कालाबाजारी पर लगाम ऑनलाइन 5 किलो की सीमा तय

एक महीने में 35 प्रतिशत बढ़े दाम, त्यौहारी सीजन से पहले सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: त्यौहारी सीजन से पहले चीनी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के बीच ऑनलाइन और रिटेल प्लेटफॉर्म्स ने इसकी खरीद पर सीमा तय कर दी है। ब्लिंकिट, जेप्टो जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर ग्राहक अब एक बार में 2 से 5 किलो तक ही चीनी खरीद सकेंगे। वहीं डीमार्ट और रिलायंस रिटेल जैसे सुपरमार्केट्स ने भी प्रति ग्राहक चीनी खरीद की सीमा निर्धारित कर दी है।

उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार, 26 अगस्त को देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत 65.05 रुपये प्रति किलो पहुंच गई। 26 जुलाई को यही कीमत करीब 48 रुपये प्रति किलो थी। इस तरह एक महीने में चीनी के दाम करीब 35.5 प्रतिशत बढ़ गए हैं। रिटेलर्स ने यह कदम चीनी की बढ़ती कीमतों और सप्लाई में कमी के बीच जमाखोरी रोकने के लिए उठाया है। चीनी उद्योग से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, सीमित स्टॉक के कारण सभी ग्राहकों को चीनी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खरीद सीमा तय की गई है।

थोक बाजार में भी चीनी की कीमतों में बड़ा उछाल आया है। थोक बाजार में चीनी के दाम 45 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 60.36 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। 20 जुलाई से 20 अगस्त के बीच चीनी की कीमतों में करीब 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे उत्पादन में गिरावट, घरेलू मांग में वृद्धि और कम बचने वाले स्टॉक को प्रमुख कारण माना जा रहा है। इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुमान के अनुसार, 2025-26 मार्केटिंग वर्ष में एथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद देश में चीनी उत्पादन करीब 279 लाख टन रह सकता है। भारत में चीनी की सालाना घरेलू खपत लगभग 280 लाख टन है। सत्र की शुरुआत में करीब 50 लाख टन का शुरुआती स्टॉक था, लेकिन उत्पादन और खपत के बीच अंतर की आशंका से बाजार में सप्लाई दबाव बढ़ गया है। अनुमान है कि सितंबर के अंत तक चीनी का क्लोजिंग स्टॉक घटकर करीब 35 लाख टन रह सकता है। त्योहारी सीजन में चीनी की मांग और बढ़ने की संभावना है। रक्षाबंधन, गणेशोत्सव, नवरात्रि और दीपावली जैसे त्योहारों में मिठाइयों और चीनी आधारित खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में चीनी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से आम परिवारों के घरेलू बजट पर असर पड़ सकता है।

चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने 10 लाख टन चीनी आयात को मंजूरी दी है। इसके अलावा चीनी आयात को कर मुक्त किया गया है और 30 सितंबर 2026 तक निर्यात पर रोक लगाई गई है। सरकार ने राज्यों को बाजारों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि जमाखोरी और सट्टेबाजी पर रोक लगाई जा सके। नए नियमों के तहत महीने में 10 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का कारोबार करने वाले डीलर 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख सकेंगे।

इंजीनियर्स से ज्यादा कमा रहे पीजी मालिक और ब्रोकर

नईदुनिया ब्यूरो, बेंगलुरु: देश की आईटी राजधानी बेंगलुरु में पीजी (पेइंग गेस्ट) कारोबार और रियल एस्टेट ब्रोकरेज से होने वाली कमाई इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। शहर में किराये के कारोबार से जुड़े लोगों की आय को लेकर एक सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें पीजी मालिकों और ब्रोकरों की कमाई की तुलना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से की गई है।

बेंगलुरु में बड़ी संख्या में आईटी कंपनियां होने के कारण हर साल हजारों युवा नौकरी के लिए शहर पहुंचते हैं। इन कर्मचारियों और छात्रों की बढ़ती संख्या से पीजी और किराये के मकानों की मांग लगातार बनी रहती है। इसी मांग ने कई लोगों के लिए पीजी कारोबार को आय का बड़ा माध्यम बना दिया है।

वायरल चर्चा के अनुसार, कुछ पीजी संचालक सीमित समय में अच्छी कमाई कर रहे हैं। वहीं, रियल एस्टेट ब्रोकर भी किराये और संपत्ति सौदों में मिलने वाले कमीशन के कारण अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। इसके चलते कई लोग पारंपरिक नौकरी की तुलना में इन व्यवसायों को अधिक लाभदायक मानने लगे हैं। शहर में आईटी सेक्टर की नौकरियों को लंबे समय से बेहतर वेतन और करियर अवसरों के लिए जाना जाता है। लेकिन बढ़ती आबादी, आवास की मांग और किराये के बाजार ने नए कारोबारी अवसर भी पैदा किए हैं।

पीजी कारोबार में कमाई कई बातों पर निर्भर करती है, जिसमें जगह, कमरों की संख्या, किराया, सुविधाएं और संचालन खर्च शामिल हैं। इसी तरह ब्रोकरों की आय सौदों की संख्या और संपत्ति की कीमतों पर निर्भर करती है। बेंगलुरु जैसे महानगरों में बढ़ती आवास मांग ने किराये और रियल एस्टेट से जुड़े कारोबार को मजबूत किया है। हालांकि, इस तरह की कमाई की तुलना किसी निश्चित नौकरी के वेतन से करना परिस्थितियों और व्यक्तिगत कारोबार के स्तर पर निर्भर करता है।

एलपीजी ई-केवायसी की डेडलाइन 31 अगस्त तक बढ़ी

सत्यापन नहीं कराने पर बुकिंग रुकने और सब्सिडी प्रभावित होने की संभावना

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए ई-केवायसी पूरा करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने आधार वेरिफिकेशन की अंतिम तारीख दूसरी बार बढ़ाई है। इससे पहले द्र-चड्ढष्ट की समय सीमा 16 अगस्त से बढ़ाकर 23 अगस्त की गई थी। तेल कंपनियों ने उन ग्राहकों को संदेश भेजना शुरू कर दिया है, जिन्होंने अभी तक अपनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। यह नियम पुराने और नए दोनों एलपीजी उपभोक्ताओं पर लागू होगा। ई-केवायसी नहीं कराने वाले ग्राहकों को भविष्य में सिलेंडर बुकिंग में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की सब्सिडी भी प्रभावित हो सकती है। लंबे समय तक सत्यापन पूरा नहीं कराने पर कनेक्शन ब्लॉक किए जाने की संभावना भी जताई गई है। ई-केवायसी की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पूरी की जा सकती है। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए उपभोक्ता संबंधित तेल कंपनी के एप या डिजिटल माध्यम का उपयोग कर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन सत्यापन गैस एजेंसी पर जाकर कराया जा सकता है।

उपभोक्ताओं को तकनीकी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। कई जगह सर्वर डाउन रहने, एप में परेशानी और धीमी प्रक्रिया के कारण सत्यापन पूरा नहीं हो पा रहा है। गैस एजेंसियों पर भीड़ बढ़ने से लोगों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है। सर्वर समस्या के कारण कई उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक सत्यापन समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है।

सुभाष चंद्रा के 22 हजार करोड़ कर्ज का निपटारा सिर्फ 6.5 करोड़ में

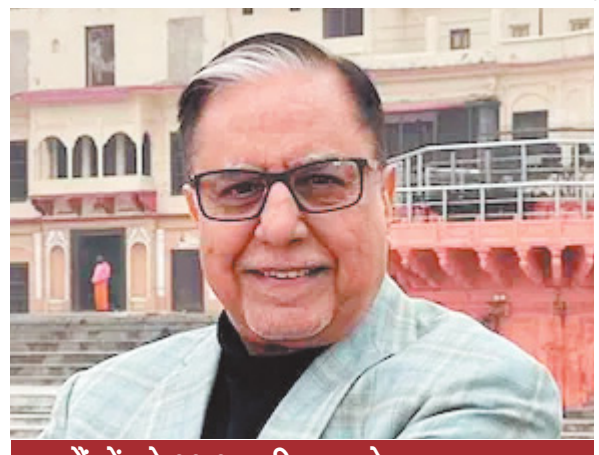

बैंकों को 99.97 प्रतिशत क्लेम का नुकसान, व्यक्तिगत गारंटी मामले में एनसीएलटी का फैसला

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने जी ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा के व्यक्तिगत दिवालियापन मामले में 6.5 करोड़ रुपये के रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद 22,006.57 करोड़ रुपये के कुल कर्ज दावे के बदले सुभाष चंद्रा को केवल 6.5 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। एनसीएलटी के इस फैसले से कर्जदाताओं को अपने करीब 99.97 प्रतिशत बकाया दावे का नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि यह नुकसान केवल सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत गारंटी से जुड़े दावों पर लागू होगा। मूल कंपनियों से बैंकों की वसूली का अधिकार बना रहेगा।

मामला एस्सेल ग्रुप की कंपनियों के लिए लिए गए कर्ज से जुड़ा है। सुभाष चंद्रा ने इन कर्जों के लिए व्यक्तिगत गारंटी दी थी। कंपनियों के भुगतान में असफल रहने के बाद यह दावे उनके खिलाफ दर्ज किए गए। यह मामला वर्ष 2016 में शुरू हुआ था, जब इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने कुछ कंपनियों को 726 करोड़ रुपये का कर्ज दिया था। वर्ष 2018 में सुभाष चंद्रा इस कर्ज के व्यक्तिगत गारंटर बने। बाद में कंपनियों के डिफॉल्ट करने पर 2022 में कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई और 2024 में एनसीएलटी में मामला आगे बढ़ा।

एनसीएलटी की दो सदस्यीय पीठ में इस मामले पर अलग-अलग राय सामने आई थी। इसके बाद तीसरे सदस्य के रूप में न्यायिक सदस्य नीलेश शर्मा को शामिल किया गया। बहुमत के आधार पर 144 पन्नों के आदेश में रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दी गई। कुछ कर्जदाताओं ने इस योजना का विरोध किया था। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने इसे अव्यावहारिक बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई थी। हालांकि एनसीएलटी ने कहा कि योजना को 80.81 प्रतिशत वोटिंग शेयर वाले कर्जदाताओं की मंजूरी मिल चुकी है, इसलिए इसे स्वीकार किया गया।

ट्रिब्यूनल ने कहा कि सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत संपत्ति का मूल्य प्रस्तावित भुगतान राशि से कम है। यदि योजना खारिज होती तो कर्जदाताओं को इससे भी कम राशि मिलने की संभावना थी। अब रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल सभी कर्जदाताओं की अंतिम सूची तैयार करेगा और 6.5 करोड़ रुपये की राशि नियमों के अनुसार वितरित की जाएगी। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर मामला बंद किया जाएगा।

बाजार में भारी उतार-चढ़ाव, सेंसेक्स 539 अंक गिरा

छह मिनट में 2200 अंक टूटा सेंसेक्स, बाद में रिकवरी के बावजूद बाजार लाल निशान में बंद

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 539 अंक टूटकर 76,934 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 117 अंकों की गिरावट रही और यह 24,091 के स्तर पर बंद हुआ। मेटल, सरकारी बैंक और मीडिया सेक्टर के शेयरों में ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। मंथली एक्सपायरी के कारण कारोबार के आखिरी समय में बाजार में तेज गिरावट आई। दोपहर 3 बजकर 19 मिनट पर सेंसेक्स करीब 2200 अंक गिर गया और 3 बजकर 21 मिनट पर यह 74,983 के स्तर तक पहुंच गया। हालांकि इसके बाद बाजार में तेजी से रिकवरी हुई। इस अचानक गिरावट ने नए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन फ्रेमवर्क को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज का आईपीओ गुरुवार से खुल गया है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 700 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। निवेशक इसमें 31 अगस्त तक बोली लगा सकेंगे। एशियाई बाजारों में गुरुवार को मिला-जुला कारोबार रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 104 अंक की बढ़त के साथ 6912 पर बंद हुआ। जापान का निक्केई 130 अंक गिरकर 66132 पर और हांगकांग का हैंगसेंग 87 अंक की गिरावट के साथ 25566 पर रहा।

अमेरिकी बाजारों में भी 26 अगस्त को कमजोरी रही थी। डाउ जोन्स 114 अंक गिरकर 53464 पर, नैस्डैक 21 अंक गिरकर 26130 पर और एसएंडपी 500 दो अंक की गिरावट के साथ 7676 पर बंद हुआ था। घरेलू निवेशकों ने पिछले सात कारोबारी दिनों में बाजार में 11,273 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं। वहीं विदेशी निवेशकों की ओर से भी 2,735 करोड़ रुपये की खरीदारी दर्ज की गई है। इससे पहले 26 अगस्त को भी बाजार में गिरावट रही थी। सेंसेक्स 183 अंक गिरकर 77,473 पर और निफ्टी 127 अंक की गिरावट के साथ 24,208 के स्तर पर बंद हुआ था।

सिर्फ 20 रुपये सालाना प्रीमियम में 2 लाख रुपये का बीमा कवर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) कम प्रीमियम में बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने वाली योजनाओं में शामिल है। इस योजना के तहत केवल 20 रुपये सालाना प्रीमियम देकर पात्र व्यक्ति 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर प्राप्त कर सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य कम आय वर्ग के लोगों को दुर्घटना के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये तक का बीमा लाभ दिया जाता है। वहीं आंशिक स्थायी विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये तक का कवर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके लिए बैंक खाते से प्रीमियम राशि ऑटो डेबिट के माध्यम से काटी जाती है। योजना से जुड़ने के लिए संबंधित बैंक में आवेदन किया जा सकता है। पीएमएसबीवाई के तहत बीमा अवधि एक वर्ष की होती है।

बिना निवेश शुरू कर सकते हैं कंटेंट क्रिएशन सोशल मीडिया बना कमाई का जरिया

मोबाइल और रचनात्मक सोच के सहारे बढ़े अवसर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: डिजिटल दौर में कंटेंट क्रिएशन युवाओं के लिए कमाई का नया माध्यम बनता जा रहा है। खास बात यह है कि इसे शुरू करने के लिए बड़े निवेश की जरूरत नहीं होती। मोबाइल फोन, इंटरनेट और रचनात्मक सोच के सहारे कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना कंटेंट तैयार कर सकता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों अलग-अलग तरह का कंटेंट तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। वीडियो, शिक्षा, मनोरंजन, खाना पकाने, यात्रा, तकनीक, फिटनेस और अन्य विषयों से जुड़े कंटेंट की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी कारण बड़ी संख्या में लोग कंटेंट क्रिएशन को करियर विकल्प के रूप में अपना रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज किसी एक विषय की अच्छी जानकारी और उसे प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाने की क्षमता है। शुरुआत में क्रिएटर्स छोटे वीडियो, पोस्ट या जानकारी आधारित सामग्री बनाकर अपनी पहचान बना सकते हैं। आज कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स को कमाई के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। विज्ञापन, ब्रांड प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से कंटेंट क्रिएटर आय अर्जित कर सकते हैं। कुछ सफल क्रिएटर्स ने इसी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाकर करोड़ों रुपये तक की कमाई की है। विशेषज्ञों के अनुसार, कंटेंट क्रिएशन में सफलता के लिए नियमितता, दर्शकों की पसंद को समझना और लगातार बेहतर सामग्री तैयार करना जरूरी है। केवल वायरल होने के बजाय लंबे समय तक दर्शकों से जुड़ाव बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। शुरुआत करने वाले लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि उनके पास महंगे कैमरे या बड़े सेटअप हों। सामान्य स्मार्टफोन से भी अच्छी गुणवत्ता का कंटेंट तैयार किया जा सकता है

स्पेशल खबर मेटा और 29 राज्यों के बीच 1.59 लाख करोड़ रुपये का समझौता, डेली लिमिट और पैरेंटल कंट्रोल लागू होंगे

अमेरिकी बच्चों को फेसबुक-इंस्टाग्राम रात में इस्तेमाल पर रोक

अमेरिकी राज्यों की ओर से कंपनी पर 200 बिलियन डॉलर तक के जुर्माने की मांग

मेटा के खिलाफ यह भी कहा गया कि इंस्टाग्राम पर दिखने वाली फिल्टर वाली तस्वीरें और दूसरों की जीवनशैली से तुलना करने की प्रवृत्ति बच्चों में अपने शरीर और व्यक्तित्व को लेकर असंतोष बढ़ा सकती है। देर रात तक सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से नींद प्रभावित होने और चिंता, अवसाद जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ने की बात भी कही गई। इसके अलावा साइबर बुलिंग, लगातार तुलना का दबाव और उम्र के अनुरूप नहीं होने वाले कंटेंट तक पहुंच को लेकर भी सवाल उठाए गए थे।

यदि मेटा यह मामला अदालत में हार जाती तो अमेरिकी राज्यों की ओर से कंपनी पर 200 बिलियन डॉलर तक के जुर्माने की मांग की गई थी। हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच 16.7 बिलियन डॉलर में समझौता हुआ। मेटा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। कंपनी का कहना है कि उसने बच्चों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं और सोशल मीडिया की लत को मान्यता प्राप्त मानसिक बीमारी नहीं माना जाता। मेटा के अलावा स्नैपचैट, यूट्यूब और टिकटॉक जैसी कंपनियां भी बच्चों और युवाओं पर सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर कानूनी मामलों का सामना कर रही हैं। हालांकि यह फैसला अमेरिका तक सीमित है, लेकिन मेटा अपने सुरक्षा फीचर्स को भविष्य में अन्य देशों में भी लागू कर सकती है।

कैलिफोर्निया, एजेंसी: अमेरिका में बच्चों और किशोरों के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम के इस्तेमाल को लेकर नए नियम लागू किए जाएंगे। मेटा और अमेरिका के 29 राज्यों के बीच हुए 16.7 बिलियन डॉलर यानी करीब 1.59 लाख करोड़ रुपये के कानूनी समझौते के बाद कंपनी को बच्चों की सुरक्षा के लिए कई बदलाव करने होंगे। ये नियम फिलहाल केवल अमेरिका में लागू होंगे। समझौते के तहत किशोरों के लिए सोशल मीडिया एप इस्तेमाल की दैनिक सीमा तय की जाएगी। इसके अलावा रात के समय फेसबुक और इंस्टाग्राम के उपयोग को रोकने के लिए फीचर लागू किए जाएंगे। बच्चों की उम्र की सख्त जांच के लिए वेरिफिकेशन टूल और माता-पिता के नियंत्रण के लिए नए फीचर्स भी जोड़े जाएंगे।

मेटा पर आरोप लगाया गया था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के डिजाइन से बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। कंपनी पर यह भी आरोप था कि उसने बच्चों की निजी जानकारी जुटाकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया। आरोपों के अनुसार, एप्स के एल्गोरिदम, नोटिफिकेशन, ऑटो-प्ले और लाइक सिस्टम बच्चों को लंबे समय तक सोशल मीडिया पर बनाए रखते हैं। इसके कारण स्क्रीन टाइम बढ़ने, सोशल मीडिया की आदत बनने और मानसिक दबाव जैसी समस्याएं सामने आईं।

बुर्ज खलीफा से महंगा बताया जा रहा जीटीए 6, लॉन्च से पहले गेमप्ले लीक

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: लोकप्रिय वीडियो गेम सीरीज ग्रैंड थेफ्ट ऑटो का नया संस्करण जीटीए 6 लॉन्च से पहले ही चर्चा में बना हुआ है। इस गेम को लेकर गेमिंग जगत में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, जीटीए 6 का बजट इतना अधिक बताया जा रहा है कि इसकी तुलना दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की लागत से की जा रही है। जीटीए 6 को इस दशक के सबसे चर्चित गेम्स में शामिल किया जा रहा है। गेम के विकास में बड़े पैमाने पर संसाधनों और तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसके कारण इसकी लागत को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं।

गेम के लॉन्च से पहले इसके कुछ हिस्सों के लीक होने की खबरों ने भी हलचल बढ़ा दी है। लीक हुए कथित गेमप्ले वीडियो और जानकारियों के बाद कंपनी की सुरक्षा और गेम से जुड़ी जानकारी को लेकर सवाल उठे हैं।

जीटीए 6 रॉकस्टार गेम्स की लोकप्रिय ग्रैंड थेफ्ट ऑटो फ्रेंचाइजी का अगला बड़ा संस्करण है। इस सीरीज के पिछले गेम जीटीए 5 को दुनियाभर में बड़ी सफलता मिली थी और लाखों खिलाड़ियों ने इसे पसंद किया था। इसी वजह से नए संस्करण से भी बड़े स्तर की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं।

जीटीए 6 को लेकर नेटफ्लिक्स पर एक्सटेंडेड प्रीमियर की चर्चा भी सामने आई है। हालांकि गेम के आधिकारिक लॉन्च और इससे जुड़ी सभी जानकारियों को लेकर कंपनी की ओर से सीमित जानकारी साझा की गई है। गेमिंग उद्योग में बड़े बजट वाले गेम लगातार बढ़ रहे हैं। बेहतर ग्राफिक्स, विशाल खुली दुनिया, नई तकनीक और अधिक वास्तविक अनुभव देने के लिए कंपनियां भारी निवेश कर रही हैं।